



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राप्तिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 1994/फाल्गुन 25, 1915

No. 121] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 1994/PHALGUNA 25, 1915

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

श्रद्धिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1994

सं. 70/94—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

मा.का.नि. 318(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1985 का 5) की अनुसूची के शीर्ष सं. 54.03 के अंतर्गत आने वाले संबूधित पोलिएस्टर फिलामेंट सूत को, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट उम पर उद्घस्तीय उत्तर उत्पाद-शुल्क से जितना तीन रुपए प्रति किलोग्राम की दर में संगणित रकम में अधिक है, छूट देती है;

परन्तु इस श्रद्धिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट केवल ऐसे संबूधित सूत की बाबत लागू होगी :—

(i) जो कि संबूधित पालिएस्टर फिलामेंट सूत के विनिर्माण के भंडार में 1 मार्च, 1994 को पड़े हुए थे, या

(ii) जो उक्त अनुसूची के शीर्ष संख्या 54.02 के अन्तर्गत आने वाले ऐसे पालिएस्टर फिलामेंट सूत (गैर-संबूधित) से विनिर्मित हैं जिसकी निकासी ऐसे पालिएस्टर फिलामेंट सूत (गैर संबूधित) के विनिर्माण के कारखाने से 1 मार्च, 1994 से पूर्ण निश्चित किया गया भाना गया है; या

(iii) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष संख्या 54.02 के अंतर्गत आने वाले आयातित पालिएस्टर फिलामेंट सूत से विनिर्मित हैं जिन पर उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन

उद्ग्रहणीय अनिवार्य मूल्क का 69 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मंदाय किया है;
परन्तु यह और किसें पानिएस्टर फिलामेंट सून पर संदर्भ शुल्क को किसी मुजरा का कंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के संघर्ष 56 के अधीन उपयोग नहीं किया गया है।

2. यह अधिसूचना 30 अप्रैल, 1994 जिसमें यह नारीख भी सम्मिलित है तक प्रभावी होगी।

[फा. स. बी-22/1/94-टीआरय्]
राजीव शर्मा, अवर मन्त्री

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 1994

No. 70/94-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 318(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5A of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts textured polyester filament yarn falling under heading No. 54.03 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1985) from so much of the duty of excise leviable thereon which is specified in the said Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of rupees three per kilogram :

Provided that the exemption contained in this notification shall be applicable only in respect of such textured yarn :—

- (i) which was lying in stock with the manufacturer of textured polyester filament yarn as on the 1st day of March, 1994; or
- (ii) which is manufactured out of such polyester filament yarn (non-textured) falling under heading No. 54.02 of the said Schedule as is established to have been cleared from the factory of manufacture of such polyester filament yarn (non-textured) before the 1st day of March, 1994; or
- (iii) which is manufactured out of imported polyester filament yarn (non-textured) falling under heading No. 54.02

of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) on which the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, has been paid at the rate of rupees sixty nine per kilogram :

Provided further that no credit of the duty paid on such polyester filament yarn (non-textured) has been availed of under Rule 56A of the Central Excise Rules, 1944.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 30th day of April, 1994.

[F. No. B22/1/94-TRU]
RAJIV SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1994

सं. 104/94—सीमाशुल्क

मा.का.नि. 319 (अ).—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अंतर्गत आने वाले ऐसे आधार (कन्टेनर्स) जो टिकाऊ हों, जब उनका भारत में आयात किया जाए,

- (क) उक्त पहली अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से, और
- (ख) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अनिवार्य शुल्क से, छृट देनी है।

परन्तु यह तब जब कि आयातकर्ता ऐसे प्रस्तुत में आंर उनकी राशि के लिए जो सहायक समाहर्ता, सीमाशुल्क द्वारा विनियिट की जाए, बंधपत्र निष्पादित करके अपने को आवढ़ करता है कि उपरोक्त आधारों (कन्टेनरों) का उनके आयात में छः मास के प्रत्यार्थ पुँः निर्धारित करेगा और उसका दस्तावेजी प्रमाण उक्त सहायक समाहर्ता, के नमाधानप्रद रूप में प्रस्तुत करेगा और ऐसा न कर पाने की दशा में उक्त आधारों पर उद्ग्रहणीय शुल्क का मंदाय करगा।

परन्तु यह और कि किसी मामले विशेष में, पूर्वोक्त छ:
मास की अवधि, पर्याप्त हेतुक दर्णात किये जाने पर, उक्त सहायक समाहर्ता ब्रारा ऐसी और अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी जो वह ठीक समझे।

[फा. सं. बी-40/1/94-टी.आर.यू.]
राजीव शर्मा, अवर मन्त्रिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 1994

NO. 104/94-CUSTOMS

G.S.R. 319(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts containers which are of durable nature, falling within the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from,

(a) the whole of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule; and

(b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act :

Provided that the importer, by execution of a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs binds himself to re-export the said containers within six months from the date of their importation and to furnish documentary evidence thereof to the satisfaction of the said Assistant Collector and to pay the duty leviable thereon in the event of the importer's failure to do so :

Provided further that in any particular case, the aforesaid period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the said Assistant Collector for such further period, as he may deem fit.

[F. No. B40/1/94-TRU]
RAJIV SHARMA, Under Secy.

